VISION IAS
R
N
29 AUG 2017
NO. 03
RECEIVED

VISION IAS

www.visionias.in

SUBJECT:	ESSAY	**Test Code:**	9 2 9
Name of Candidate	RHEECHA RATNAM		
Medium Hindi/Eng.	HINDI	Registration Number	4 6 8 0
Center	Rajendra Nagar	Date	2 9 0 8 1 7

INDEX TABLE

Q. No.	Page No.	Maximum Marks	Marks Obtained

Total Marks Obtained:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
4. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
6. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जैसा कि हम जानते हैं, वैश्वीकरण समाप्त हो गया है

वैश्वीकरण जिसका अर्थ है 'विश्व का अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण', हाल के वर्षों में इसके विषय में विभिन्न स्तर पर विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

इस निबंध के माध्यम से हम निम्नलिखित प्रश्नों का अवलोकन करेंगे।

वैश्वीकरण का इतिहास व इसकी जड़ें किसमें व्याप्त है?

वैश्वीकरण का विभिन्न देशों के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा?

क्या 1991 पश्चात के अति वैश्वीकरण (Hyper globalisation) का दौर समाप्त हो गया है?

वैश्वीकरण द्वारा हाल के वर्षों में सामना की जा रही विभिन्न चुनौतियाँ क्या है?

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वैश्वीकरण का अर्थ सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होते हैं।

आधुनिक काल के इतिहास के साथ, वैश्वीकरण की जड़ें जुड़ी हैं। पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा औपनिवेशवाद व मुक्त व्यापार के माध्यम से, सुदूर देशों में, स्थित अपने उपनिवेशों को वैश्विक अर्थतंत्र से जोड़ा गया।

भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल (1813-1858), में, इसे ब्रिटिश कारखानों में निर्मित वस्तुओं का उपभोक्ता व कच्चे माल का निर्यातकर्ता देश बना दिया गया।

इसके साथ ही, औपनिवेशिक शासन ने सावधानी के साथ भारतीय समाज में हस्तक्षेप की नीति का आरंभ किया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रह्मण्यम ने वैश्वीकरण के चार चरणों की पहचान की है, जिसमें 1991 के पश्चात हुए वैश्वीकरण को उन्होंने अति वैश्वीकरण (Hyper globalisation) कहा है।

द्वितीय युद्ध पश्चात, पश्चिमी देशों में वैश्वीकरण को लेकर तीव्रता दिखाई तथा इस नीति का प्रसार, पूर्वी एशियाई देशों - चीन, दक्षिण कोरिया इत्यादि में हुआ।

पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों - चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर इत्यादि ने वैश्वीकरण को अपनाते हुए, अपने देशों में मुक्त पूंजी निवेश को आकर्षित किया। इन देशों ने, निर्यात आधारित संवृद्धि (export led growth) का लाभ उठाकर, अपने देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखो)

वैश्वीकरण के नियमों के संचालन में, पूरे विश्व में एकरूपता लाने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता मालूम पड़ी। अतः ही विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों - विश्व बैंक, WTO व IMF ने, अमेरिका के नेतृत्व में इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया।

यहाँ WTO, वैश्विक स्तर पर व्यापार के नए नियमों का निर्माण कर रहा है, वहीं IMF व विश्व बैंक शर्तों के साथ विकासशील देशों को वहन सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।

भारत ने भी 1991 में, उदारीकरण के साथ वैश्वीकरण को अपनाया। भारत सेवाओं के प्रमुख निर्यातक देश के रूप में स्थापित हुआ है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप, भारत की आर्थिक संवृद्धि दर में वृद्धि हुई तथा रोजगार के नए अवसर खुले हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वैश्वीकरण पश्चात्, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, जहाँ सेवाओं का अनुपात (50%) से अधिक हुआ है, वहीं कृषि का योगदान घट गया है।

वैश्वीकरण का प्रभाव सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि संस्कृति के अमेरिकीकरण की चर्चा प्रायः इससे जुड़ी हुई है। विश्व भर में नगरीय सभ्यताओं में एकरूपता दृष्टिगोचर हो रही है।

विभिन्न पर्यावरण के विषयों से जुड़े विषयों पर भी, अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास किया गया है जिसका सफल उदाहरण है:- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल व पेरिस जलवायु समझौता।

प्रश्न यह उठता है कि, जब वैश्वीकरण से जुड़े विभिन्न सफल उदाहरण उपस्थित हैं, तो क्यों वैश्वीकरण के समाप्ति की चर्चा की जा रही है। इस प्रश्न पर हम दो पक्षों/सन्दर्भ से विचार

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

करेंगे - भारतीय पक्ष व अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में।

भारतीय संदर्भ में 1991 पश्चात, देश की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद, वैश्वीकरण को लेकर विभिन्न प्रश्न उठाए जाते रहे हैं।

वैश्वीकरण, समावेशी विकास प्रक्रिया में असफल सिद्ध हुआ है। भारत में वैश्वीकरण के कारण गरीबों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है, बल्कि वे विकास प्रक्रिया में पीछे छूट गए हैं।

भारत में 2000-2008 का दौर, आर्थिक संवृद्धि का दौर था, लेकिन हाल के वर्षों में इसे, रोजगारविहीन संवृद्धि का दौर कहा जा रहा है।

वैश्वीकरण पश्चात भारत में, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन में कम हुआ है, बल्कि 70% से

अधिक नौकरियों का सृजन, अनौपचारिक क्षेत्र में हुआ है, जो सामाजिक सुरक्षा, काम की सुरक्षा, अच्छा वेतन नहीं उपलब्ध कराती है।

इसके अतिरिक्त, वैश्वीकरण के कारण, भारतीय बाज़ार, विदेशी वस्तुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसका व्यापक प्रभाव सूक्ष्म व लघु उद्योगों (MSME) पर पड़ा है।

भारत में कृषि क्षेत्र को वैश्वीकरण से कोई लाभ प्राप्त होता नहीं दिखता है, बल्कि इस दौर में सकल पूंजी निवेश की मात्रा (कृषि क्षेत्र में) कम हुई है।

हाल के वर्षों में भारतीय युवाओं के डिप्रेशन व अकेलेपन की समस्या में वृद्धि को, वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव से जोड़ कर देखा जा रहा है। शहरों में एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि, जिसके कारण, वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा पर प्रश्न उत्पन्न हुए हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, वैश्विक आर्थिक संकट (2008) पश्चात, वैश्वीकरण के प्रभावों पर चर्चा प्रारंभ हो गई।

विकसित देश, विकासशील देशों के लोगों के हाथों, विनिर्माण व सेवा क्षेत्र की नौकरियां खोने को लेकर, हाल के वर्षों में अधिक सक्रिय हुए हैं।

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की विजय तथा उनके द्वारा अपनाई जा रही संरक्षणवादी नीति का प्रभाव, आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर पड़ेगा।

ट्रंप ने अमेरिका को ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशीप से बाहर कर दिया, तथा H1B वीसा पर नए नियमों को स्वीकृति दी गई है।

इंग्लैंड के यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के कारण (Brexit) को भी, वैश्वीकरण के संदर्भ में समझा जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में, 2017 पश्चात, वैश्वीकरण के विषय में चर्चा की गई है। आने वाले वर्षों में पूरे विश्व की राजनीतिक क्षमता का प्रभाव वैश्वीकरण के विकास से जुड़ा होगा। जहाँ चीन के उत्पादों के निर्यात के कारण विकसित देशों में हुई रोजगार की हानि को प्रतिसंतुलित करना मुश्किल रहा है, वहीं भारत के सेवा निर्यात के कारण विकसित देशों में हुई रोजगार हानि को उच्च कौशल युक्त सेवाओं के द्वारा प्रतिसंतुलित किया जा सकता है।

भारत को यदि आने वाले वर्षों में 7-8% की आर्थिक संवृद्धि दर प्राप्त करनी है, तो यह आवश्यक होगा कि, वैश्वीकरण की नीति वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य हो। आने वाले वर्षों में भारत को, वैश्वीकरण के समर्थन में सामने आना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नकदीरहित अर्थव्यवस्था : संभावनाएं मुद्दे एवं चुनौतियां

2016 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित विमुद्रीकरण का मध्यमवर्ती लक्ष्य, भारत को नकदीरहित अर्थव्यवस्था बनाना भी था।

हाल के दिनों में भारत के नकदीरहित अर्थव्यवस्था में विकसित होने के संबंध में विभिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं।

इस निबंध के माध्यम से हम निम्नलिखित प्रश्नों का अवलोकन करेंगे :-

भारत में नकदीरहित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या मुद्दे विद्यमान हैं?

भारत नकदीरहित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित होने में किन चुनौतियों का सामना कर रहा है?

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विमुद्रीकरण पश्चात् केंद्र सरकार ने कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न योजनाएँ व उप शुरु किए - 'डिजिधन व्यापार योजना', 'भीम एप' (भीम-आधार पे) इत्यादि

सरकार देश में नकद के प्रचलन को कम करने की दिशा में कार्य कर रही है।

प्रश्न यह उठता है कि नकद के प्रचलन को कम करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है?

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, जिन देशों में, नकद का प्रचलन अधिक होता है; वहाँ भ्रष्टाचार व अवैध कार्यकलापों की संभावना अधिक रहती है।

भारत में नकद के अनुपात में भ्रष्टाचार का अनुपात, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में कम है। इसके दो कारण सुझाए गए हैं - या तो भारत में भ्रष्टाचार का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अनुपात और अधिक है, या फिर भारत में नकद का प्रचलन वैध कार्यों हेतु किया जाता है।

जैसे-जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है; उस अर्थव्यवस्था में नकद का प्रचलन कम होता जाता है। भारत में, नकद के प्रचलन में उस अनुपात में कमी नहीं आई है।

प्राइस वाटर हाउस के आंकड़ों के अनुसार भारत में नकद व जीडीपी का अनुपात (cash/gdp) 12% है, जो इस स्तर की विभिन्न विकासशील देशों के अनुपात से अधिक है।

भारत में नकद का प्रचलन, अधिक क्यों है?

भारत में नकद के अधिक प्रचलन के विभिन्न कारण सुझाए गए हैं,

उदाहरण- नकद संव्यवहार में व्यक्ति की गोपनीयता बनी रहती है,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नकद संव्यवहार, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुफ्त है, भले ही इसके सामाजिक लागत ब्याज हो, व्यवहार संबंधी कारण, जहाँ सुविधा नकद की तरफ अधिक होता है, इत्यादि।

भारत में कैसलेस अर्थव्यवस्था से संबंधी मुद्दे, भी नकद संव्यवहार का एक प्रमुख कारण है।

भारत में डिजिटल अवसंरचना की कमी, जिसके कारण भारत के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, कैसलेस अर्थव्यवस्था से जुड़ी मुख्य चुनौती है।

भारतनेट परियोजना के माध्यम से देश के 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ने संबंधी कार्य, अभी पूरा नहीं हुआ है।

विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट - 2016 में भारत में विद्यमान, डिजिटल डिवाइड की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चर्चा की थी।

भारत में, अशिक्षित लोगों की एक बड़ी संख्या, डिजिटल साधनों का प्रयोग करने में असक्षम है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड का अनुपात अधिक होने के कारण, इन क्षेत्रों में लोग, नकद पर अधिक निर्भर हैं।

भारत में लैंगिक डिजिटल डिवाइड की समस्या भी गंभीर है, जहाँ महिलाओं द्वारा डिजिटल साधनों के प्रयोग द्वारा आर्थिक संव्यवहार करने का अनुपात कम है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए व्यापारियों के पास POS (Point of sale) मशीनों की उपलब्धता भी एक प्रमुख चुनौती है, भारत में POS मशीनों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

का संकेंद्रण, वैश्विक अनुपात की तुलना में बेहद कम है।

कैशलेस संव्यवहार हेतु क्रेडिट/डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट के प्रयोग, NEFT/RTGS द्वारा नकद हस्तांतरण में, सेवा प्रदाता कंपनियां ग्राहकों से पैसे लेती हैं। इसके कारण ग्राहक व व्यापारी दोनों ही नकद संव्यवहार को बढ़ावा देते हैं।

भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था हेतु आधारिक अवसंरचना की कमी, एक प्रमुख बाधा है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न रिपोर्ट्स ने भारत में नकद के अधिक प्रचलन को, भारतीयों के संव्यवहार से जोड़ा है। भारत में लोग नकद में धन जमा करने के इच्छुक होते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने हेतु, हाल के दिनों में सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं

स्मार्ट फोन धारकों के लिए भीम ऐप, बेसिक हैंडसेट धारकों के भीम USSD व बिना फोन वाली आबादी के लिए भीम-आधार पे, जिसमें अपने बायोमैट्रिक (अंगूठे) के द्वारा ग्राहक कैशलेस भुगतान कर सकेंगे।

देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था के नियामकीय अवसंरचना में सुधार हेतु, केंद्र सरकार ने रतन वातल समिति का गठन किया था।

इस समिति ने अपने सुझावों में स्वतंत्र भुगतान बोर्ड के

गठन व अन्य संबंधित सुझाव दिए हैं; जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

हाल ही में, NPCI द्वारा भारत QR code को लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से विभिन्न बैंकों के ग्राहक एकीकृत QR code के माध्यम से कैशलेस भुगतान कर पाएंगे।

स्पष्ट है कि सरकार भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने हेतु विभिन्न कदम उठा रही है, लेकिन इस संबंध में विभिन्न विषयों का समाधान आवश्यक होगा।

स्वीडन, जिसने 2020 तक स्वयं को कैशलेस अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की घोषणा की है, के द्वारा हाल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के वर्षों में साइबर वित्तीय अपराधों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत में कैशलेस वित्तीय अर्थतंत्र की सुरक्षा हेतु, एक सुरक्षित साइबर सुरक्षा तंत्र का गठन आवश्यक होगा।

पिछले वर्ष, SBI के लाखों ग्राहकों के डेबिट कार्ड से जुड़ी सूचनाओं के लीक होने का कारण, हिताची पेमेंट उपकरण को बताया गया।

भारत में साइबर अपराधों से लड़ने के लिए विशेष तंत्र की अनुपलब्धता एक बड़ी चुनौती है।

इसके अतिरिक्त भारत, इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी वस्तुओं के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संबंध में विदेशी आयातों पर निर्भरता।

कैशलेस अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि भारत स्वयं को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण में आत्मनिर्भर का ले।

विदेशी उत्पादों पर निर्भरता आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक सुभेद्यता का कारण बन जाएगी, जिसके कारण भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

हाल ही में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भारत को कैशलेस की जगह लेसकैश अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने संबंधी विचार प्रस्तुत किया है।

चूंकि भारत की जनसंख्या व विषमता को देखते हुए,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

यह आवश्यक होगा कि, ऐसी नीति का निर्माण किया जाए, जिससे समाज के किसी भी तबके को हानि न पहुँचे।

विमुद्रीकरण के दौरान, लोगों को हुई असुविधा की खबरें आती रही थीं।

सरकार द्वारा नेशनल अर्थव्यवस्था की दिशा में चरणबद्ध तरीके से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार को कैशलेस संव्यवहार पर विभिन्न छूटें, इनाम इत्यादि की घोषणा, ऐसे प्रोत्साहन देने हेतु की जानी चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आँकड़ों के अनुसार, प्रत्येक भारतीय के पास 2 डेबिट / ATM कार्ड हैं, जो चीन के अनुपात में कम है, वहीं भारत में इन कार्डों का प्रयोग ATM से पैसे निकालने हेतु अधिक किया जाता है।

भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था के विकास हेतु हाल के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, जो देश में भ्रष्टाचार, काले धन की समस्या को भी कम करेगा, हालांकि आवश्यक है कि सरकार, इस दिशा में सही व संतुलित कदम उठाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

• Cashless economy
↳ Recent move – demonetization
↳ India – behavioral
– infrastructure lacking
– digital divide
– cash v/s cashless

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

• Globalisation – defn
↓ History ↓ Geography ↓ Polity ↓ ↓ Economy ↓ Environment
Polity ↓ America + multinational organizations – IMF/Worldbank; culture; Climate +

Globalization
↳ इतिहास - औपनिवेशिक काल से आरंभ।
↳ 1991 - अति वैश्वीकरण (Hyper globalization)
L वस्तुओं - चीन
L सेवाओं - भारत

↳ भूगोल - पूरे विश्व में फैला
L पूर्वी देशों + एशिया + अफ्रीका।
L ~~export~~ |-

↳ Polity → IMF + World Bank + WTO.

↳ Economics → Export led growth
↳ India 2000 boom period

↳ Culture → अमेरिकीकरण

↳ Environment → Environmental Climate

↓ global → वैश्विक आर्थिक संकट 2008
↓ वैश्वीकरण
↳ हाल के वर्षों में विश्व की राजनीतिक स्थिति
↳ अमेरिका - ट्रंप संरक्षणवादी नीतियों को प्रोत्साहन
– Brexit.